

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 21 मई, 2010

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में किंक्रेग तिराहे का विस्तारीकरण के अन्तर्गत पार्किंग हेतु एक अतिरिक्त तल का निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद देहरादून के अन्तर्गत अम्बाला-मसूरी मोटर मार्ग के किमी0 214 में किंक्रेग तिराहे का आर0सी0सी0 कॉलम एवं दीवार द्वारा चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु रू0 57.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0: 2330 / 111(2) / 08- 16(एम0एल0ए0) / 2007 दिनांक 15 जुलाई, 2008 द्वारा प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0:-2920 / 282 सी-9 / 10 दिनांक 27-04-2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन, लागत रू0 114.11 लाख (पूर्व स्वीकृत लागत रू0 57.06 सहित) पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 108.23 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0: 2330 / 111(2) / 08- 16(एम0एल0ए0) / 2007 दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रदान की गई स्वीकृति रू0 57.06 लाख की धनराशि को घटाते हुए, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 51.17 लाख (रू0 इक्यावन लाख सतरह हजार मात्र) की पुनरीक्षित वृद्धि में इस अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब उक्त कार्य हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। यह शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी।

3- पुनरीक्षित आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

4- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

प्रदीप सिंह रावत



5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। अब पुनः नये आगणन प्रस्तुत किये जाने पर परिवर्तित आगणनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्च्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

12- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

13- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

14- उक्त योजना पर व्यय अनुदान सं०:-22 राज्य योजना, के अन्तर्गत (मार्ग के चालू कार्य) के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से किया जायेगा।

15- यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली सं०:- 29(प्रा०आ०)/2006 एवं 07(प्रा०आ०)/2005 में प्राप्त वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

धन

भवदीय,

प्रदीप सिंह रावत

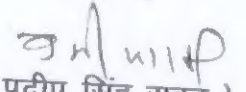
( प्रदीप सिंह रावत )  
उप सचिव

संख्या:- 2149 (1) / 111(2) / 10-16(एम0एल0ए0) / 2007 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. ✓ निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
( प्रदीप सिंह रावत )  
उप सचिव